प्रेस विज्ञप्ति

28.09.2018

श्रमिकों की राष्ट्रीय कन्वेंशन का मेहनतकश जनता को आह्वान

बीजेपी नेतृत्व की एनडीए सरकार की जन–विरोधी, मजदूर–विरोधी, राष्ट्र–विरोधी नीतियों की चुनौतियों का सीधे मुकाबला करें

दस श्रमिक संगठनों – इंटक, एटक, एच.एम.एस, सीटू, ए.आई.यू.टी.यू.सी, टी.यू.सी.सी, एक्टू, सेवा, एल.पी.एफ तथा यू.टी.यू.सी एवं स्वतंत्र फेडरेशनों व एसोसिएशनों के द्वारा संयुक्त तौर पर आज 28 सितंबर 2018 को मावलंकर हाल दिल्ली में आयोजित श्रमिकों की राष्ट्रीय कन्वेंशन में औद्योगिक व सेवा क्षेत्र के राष्ट्रभर से श्रमिक हिस्सा लेने पहुंचे। इनमें केंद्रीय व राज्य सरकारों के कर्मचार, समेत रेलवे, डिफेंस, स्वास्थ्य, शिक्षा, जल विभाग, पोस्ट व स्कीम वर्कर थे, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में से बैंक, इंशोरेंस, टेलीकॉम, तेल, कोयला, अन्य खनन क्षेत्र, सार्वजनिक ट्रांसपोर्ट कर्मी थे, तथा असंगठित क्षेत्र से निर्माण, बीड़ी, स्ट्रीट वेंडर, गृह उद्योग, घरेलू कामगार, फैक्टरी मजदूर, प्रवासी मजदूर, कृषि मजदूर, रिक्शा चालक, ऑटो रिक्शा, टैक्सी ड्राइवर्स इत्यादि सभी मजदूर यूनियन सम्मिलित हुए। उन्होंने केंद्र सरकार व कुछ बीजेपी शासित राज्य सरकारों की कार्पोरेट परस्ती, जन विरोधी–मजदूर विरोधी नीतियों के चलते देश की बिगड़ती हुई अर्थव्यवस्था जिसके कारण कामकाजी लोगों की जीविका पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है, इस पर गहरी चिंता प्रकट की।

इस राष्ट्रीय कन्वेंशन की अध्यक्षता करने वालों में शामिल थे, अशोक सिंह, रामेन्द्र कुमार, एस एन पाठक, के. हेमलता, आर.के.शर्मा, प्रवीर बनर्जी, लता, संतोष राय, के.नटराजन तथा शत्रुजीत सिंह।

राष्ट्रीय कन्वेंशन में वक्तव्य रखने में शामिल थे– डॉ. संजीव रेड्डी (इंटक), अमरजीत कौर (एटक), हरभजन सिंह सिद्धू (एचएमएस), तपन सेन (सीटू), सत्यवान (एआईयूटीयूसी), जी.आर.शिवशंकर (टीयूसीसी), सोनिया जार्ज (सेवा), राजीव डिमरी (एक्टू), पेची मुथु (एलपीएफ), अशोक घोष (यूटीयूसी), शिवा गोपाल मिश्र (एआइआरएफ), और गुमान सिंह (एनएफआइआर)।

यह कन्वेशन गंभीर चिंता के साथ संज्ञान लेती है कि सरकार लगातार न्यूनतम वेतन, सार्वजनिक सामाजिक सुरक्षा, स्कीम वर्कर्स को वर्कर्स का दर्जा के साथ–साथ वेतन और अन्य सुविधाओं, वित्तीय सेक्टरों समेत पब्लिक और सरकारी क्षेत्र में निजीकरण के खिलाफ, व्यापक पैमाने पर ठेकाकरण के खिलाफ, आईएलओ कन्वेंशन 87 और 98 का अनुमोदन करने की मांग आदि पर 12 बिन्दु मांग पत्र, जो कि देश के पूरे ट्रेड यूनियन आंदोलन द्वारा संयुक्त रूप से अपनाई गयी है, को अहंकारी ढंग से अनदेखा कर रही है। होमवर्क पर 179 और घरेलू काम पर 189 आईएलओ कन्वेंशन की अभी तक पुष्टि नहीं की गई है।

कन्वेंशन ने सरकार द्वारा 44 श्रम कानूनों को खत्म कर 4 मालिक परस्त श्रम कोड लाने के निर्णय का पुरजोर विरोधी किया। फिक्स्ड टर्म एम्पलायमेंट कानून को जो कार्यकारिणी आदेश के द्वारा लाया गया है उसकी कड़ी भर्त्सना की। कन्वेंशन ने नई पेंशन योजना पर आक्रोश जाहिर करते हुए पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग की। संघर्षरत किसानों के साथ व 16–17 सितंबर की रात से राजस्थान के ट्रांसपोर्ट कर्मचारियों की चल रही हड़ताल के साथ एकजुटता जारी की। सम्मेलन में एक विशेष प्रस्ताव पारित करके राजस्थान रोडवेज, यामाहा, रॉयल एनफील्ड, और मिकोंगसिंह ऑटोमोटिव कंपनी में जारी हड़तालों का समर्थन किया।

इस नेशनल कन्वेंशन ने सरकारी तंत्र की मदद से समाज में सांप्रदायिकता और फूट डालने की जो साजिश हो रही है, उस की कड़े शब्दों में निंदा की, भा.ज.पा की सरकारें, विरोधी मत और अभिव्यक्ति स्वतंत्रा के खिलाफ एन.एस.ए., यू.ए.पी.ए. जैसे घिनौने कानूनों का तथा सी.बी.आई, एन.आई.ए, आई.टी जैसी एजेंसियों का खुले आम इस्तेमाल कर रही है। शांतिप्रेमी, धर्मनिरपेक्ष जनता असुरक्षितता और दहशत भरे माहौल का अनुभव कर रही है। मजदूर वर्ग ने इस के खिलाफ पूरी संजिदगी से आवाज उठने का निर्णय लिया।

इस सरकार की जनविरोधी, मजदूर विरोधी तथा देशविरोधी, पॉलिसियां न सिर्फ श्रमिकों पर बोझ डाल रही है, बल्कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां और उनके चमचे देशी कॉर्पोरेट्स मिलकर देश की अर्थव्यवस्था की नींव ही उखाड़ रहे हैं, अपने देश की उत्पादन क्षमता को ही खत्म कर रहे हैं। जनहित की पॉलिसियां अमल में लाने के लिए, यह जनविरोधी और देशविरोधी नीतियों के चलाने वाली सरकार को निकाल बाहर करना ही होगा और इसलिए जरूरी है कि मजदूर वर्ग के इस गठबंधन को अपने संघर्ष अधिक तीव्र करने होंगे। इसलिए यह नेशनल कन्वेंशन निम्नलिखित कार्यक्रम को स्वीकार करता है।

1. **अक्टूबर/नवम्बर 2018 के दरम्यान राज्य, जिला और उद्योग/क्षेत्र के स्तर पर संयुक्त कन्वेंशन का आयोजन**
2. **उद्योग–स्तर पर संयुक्त तरीके से सभाएं, रैली आदि जो नवम्बर–दिसम्बर, 18 के दरम्यान हड़ताल की तैयारी में किए जाए**
3. **17–22 दिसम्बर, 2018 के दरम्यान प्रदर्शन करते हुए हड़ताल की नोटिस देना**
4. **8 और 9 जनवरी 2019 को दो दिन की देशव्यापी हड़ताल**

इस नेशनल कन्वेंशन ने तमाम श्रमिक जनता से अपील की है कि आप किसी भी संगठन, क्षेत्र या राज्य के हो, एक साथ मिलकर इस कार्यक्रम को सफल बनाएं।

इंटक	एटक	एच एम एस	सीटू	एआईयूटीयूसी
टीयूसीसी	सेवा	एआईसीसीटीयू	एलपीएफ	यूटीयूसी

एवं विभिन्न सैक्टर की स्वतंत्र फैडरेशन्स/एसोसिएशन